बिहार में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव

2005. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"** :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कब हुये थे;

(ख) बिहार में इतनी लम्बी अवधि तक चुनाव न होने पाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चुनावों में इस तरह की असाधारण देरी 73वें एवं 74वें संविधान विधेयक का घोर उल्लंघन नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है/करने का विचार रखती है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) ग्राम पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चुनाव क्रमशः 1978, 1979 और 1980 में करवाये गये थे। संविधान के 74वें संशोधन के लागू होने के बाद नगर निगमों के चुनाव नहीं कराये गये हैं। 74वें संशोधन से पहले नगर निगमों के चुनाव भिन्न-भिन्न नगर-पालिकाओं के लिये अलग-अलग समयों पर कराये गये थे।

(ख) बिहार राज्य में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव नहीं कराये जा सके क्योंकि कई विशेष अनुमति याचिकायें भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़ी हैं।

(ग) बिहार में पंचायत और नगर-पालिका के चुनाव करवाना तब तक संभव नहीं होगा, जब तक कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ से विशेष अनुमति याचिकाओं पर निर्णय नहीं हो जाता है।

(घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि चूंकि विशेष अनुमति याचिकाओं को निपटाने के लिये भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के साथ-साथ बिहार पंचायती राज अधि-नियम, 1993 की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता है, इसलिये इस पर निर्णय संविधान पीठ द्वारा लिया जाना चाहिये। सरकार ने संविधान पीठ का शीघ्र गठन करवाने तथा मामले की शीघ्र सुनवाई करवाने के लिये आवेदन देकर इस मामले को उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ विधि मंत्रालय में भी उठाया है।

Assistance to drinking water projects in Andhra Pradesh

2006. SHRI Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government of Andhra Pradesh has requested for assistance to drinking water projects of Mahaboobnagar and Nalgonda districts through the World Bank; and

(b) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) Yes, Sir. A proposal of the Government of Andhra Pradesh for an Intigrated Rural Water Supply and Environmental Sanitation Project to be implemented in the districts of Mahaboobnagar and Nalgonda has been received in this Ministry. The proposal has been forwarded to Department of Economic Affairs for posing it to the World Bank for possible assistance.